



ट्रांसजेंडर अधिकारों की तुलना में विधायी अधिनियम

डॉ. मीना कुमारी

गेस्ट फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी

ABSTRACT

विधायिका द्वारा विभिन्न कानूनों का अधिनियमन संवैधानिक प्रावधानों का परिणाम है जो इस वर्ग के पक्ष में अधिकार स्थापित करके कानूनी वैधता प्रदान करता है। प्रासंगिक अधिनियम जो इस वर्ग की पहचान स्थापित करते हैं, हालांकि विशेष रूप से नहीं, नीचे चर्चा की गई है।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897

अधिनियम 30 के तहत 'व्यक्ति' शब्द एक व्यापक दायरे से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। उक्त अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि मर्दाना लिंग को आयात करने वाले शब्दों को महिलाओं को शामिल करने के लिए लिया जाएगा। जब तक विषय या संदर्भ में कुछ भी विरोधाभासी न हो, यह शर्त स्वयं वैधानिक दिशा से वातानुकूलित है। उपरोक्त प्रावधानों को एक सामंजस्यपूर्ण पठन दिया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से बताता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा के दायरे में आएंगे।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

इस अधिनियम की धारा 5 एक हिंदू विवाह की अनिवार्यताओं को निर्धारित करती है। इस खंड के अनुसार, दो हिंदू, जिनमें से एक को दुल्हन और दूसरे दूल्हे के रूप में पहचाना जा सकता है, एक विवाह को संपन्न कर सकते हैं, जब तक कि यह धारा के उपधारा (i), (ii), (iii), (iv) तथा (v) द्वारा वर्जित न हो। इसलिए, ट्रांससेक्सुअल, जिन्होंने अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में अपने सेक्स को फिर से असाइन किया है और कानूनी तौर पर खुद को महिला या पुरुष होने की पहचान कर सकते हैं, यानी दुल्हन या दुल्हन अपनी शादी को कानूनी रूप से मान्यता दे सकते हैं। ऐसा विवाह भी किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा चुनौती का विषय नहीं है, क्योंकि विवाह को अमान्य करने या तलाक के लिए याचिका केवल विवाह के पक्षकारों द्वारा ही लाई जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार केवल वर और वधू का विवाह ही वैध और मान्यता प्राप्त है। शब्द "दुल्हन" और "दुल्हन" लिंग शब्द हैं। यह आवश्यक रूप से उनकी शादी के दिन "महिला" और "पुरुष" का अनुवाद करता है। इस प्रकार, यह तीसरे लिंग के लिए विवाह को कोई मान्यता प्रदान नहीं करता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955

अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण को निर्धारित करता है जबकि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से लिंग या लिंग पहचान को नागरिकता प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित करता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतदाताओं के रूप में नामांकित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष उपाय किए गए हैं।

हिन्दू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, (एवएएमए) 1956

दत्तक ग्रहण संबंधों के उन रूपों में से एक है जिसे परिवार की छतरी के नीचे मान्यता प्राप्त है, और इस प्रकार यह परिवार के मौलिक अधिकार का हिस्सा बन जाता है। व्यक्तिगत कानूनों के तहत, केवल हिंदुओं को गोद लिए गए बच्चे के कानूनी माता-पिता के रूप में कार्य करने की अनुमति थी। भारत में किसी अन्य पर्सनल लॉ ने इस तरह के अधिकार को मान्यता नहीं दी है। हालांकि, किशोर न्याय (बाल की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, एक धर्मनिरपेक्ष कानून के रूप में कार्य करता है, जिसने किसी भी धार्मिक संप्रदाय के लोगों को बच्चा गोद लेने का प्रावधान किया है। ट्रांसजेंडरों की स्थिति के विश्लेषण के लिए, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम और किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण)

अधिनियम, 2015 दोनों अनिवार्य हैं: हिंदू ट्रांससेक्सुअल अपने लिंग को फिर से सौंपने के बाद पुरुषों के मामले में धारा 7 और महिलाओं के मामले में धारा 8 के तहत शर्तों को पूरा करने के बाद वैध रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। HAMA के तहत गोद लेने के लिए किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं है, और ट्रांससेक्सुअल अपने माता-पिता से निजी तौर पर बच्चों को वैध रूप से गोद ले सकते हैं। हालांकि, गोद लेने के मामले में जिसमें उनके प्राकृतिक अभिभावक शामिल नहीं होते हैं, उच्च स्तर की जाँच होती है जहाँ ट्रांससेक्सुअल को अदालत के सामने यह साबित करना होता है कि वे HAMA की धारा 7 या धारा 8 के तहत वास्तव में पात्र हैं। धारा 7 और 8 के तहत HAMA एक वैध दत्तक ग्रहण को केवल तभी मान्यता देता है जब यह एक पुरुष या महिला द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार, तीसरे लिंग इस अधिनियम के आवेदन के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 के आधार पर, हिजड़ों में रीट की प्रथा के आधार पर गोद लेने को सीमा शुल्क पर अधिनियम के प्रावधानों को अधिभावी शक्तियाँ प्रदान करके अवैध कर दिया गया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

इस अधिनियम की धारा 41(6) एक क्रांतिकारी सुधार है जो किसी भी "व्यक्ति" को बच्चा गोद लेने का अधिकार प्रदान करता है, न कि "पुरुष" या "महिला" को। इसके अतिरिक्त, यह तीसरे लिंग के जोड़े को बच्चा पैदा करने का अधिकार भी प्रदान करता है (यदि उन्हें एक जोड़े के रूप में मान्यता प्राप्त है) क्योंकि उन्हें प्रावधान के तहत एक निःसंतान दंपति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

इस अधिनियम 39 का उद्देश्य उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण तथा उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने और अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, संपत्ति रखने या निपटाने, सार्वजनिक या निजी का्यालय रखने और पहुंच केंद्रों में भेदभाव को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। और सार्वजनिक सेवाओं और लाभों का उपयोग। इस अधिनियम के नपुंसक प्रावधानों का उल्लेख आगे की चर्चाओं में किया गया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों कि जीवन, स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की रक्षा करना भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है और इसका तात्पर्य यह भी है कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहने या केवल पशु अस्तित्व से कुछ अधिक है। इसलिए, जीवन के अधिकार में जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो एक व्यक्ति के लिए सम्मान के साथ जीने और अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हैं। संविधान में प्रतिष्ठापित अनुच्छेद 21 एक नकारात्मक अधिकार है और यह प्रावधान करता है कि राज्य को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहरहाल, काफी संख्या में मामलों में, न्यायपालिका

ने राज्य के सकारात्मक दायित्वों के संदर्भ में अधिकार की व्याख्या की है ताकि सम्मान के साथ जीने और जीवन का बेहतर आनंद लेने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। फ्रांसिस कोरली में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को व्यापक अर्थ दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि सही जीवन का अर्थ केवल "पशु अस्तित्व" नहीं है, बल्कि इसमें 'मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने इस प्रकार अनुच्छेद 21 के तहत विचार किए जाने के लिए व्यापक विनिर्देश दिए हैं।

अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या जीवन कि अधिकार में अंग की रक्षा के लिए राज्य का दायित्व शामिल है या इससे अधिक कुछ। दिए गए मामले में यह देखा गया कि अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है और यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़े, आश्रय, पढ़ने, लिखने, सीखने और व्यक्त करने की सुविधा, आंदोलन की स्वतंत्रता के अधिकार का पालन करता है। और दूसरों के साथ जुड़ाव और ऐसा आचरण या व्यवहार करने का अधिकार भी जो मानव स्वयं की न्यूनतम अभिव्यक्ति का गठन करता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित सकारात्मक अधिकारों की प्राप्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार और ऐसे आचरण को करने का अधिकार जो स्वयं की न्यूनतम अभिव्यक्ति का गठन करता है, के मूल सिद्धांत हैं सम्मान के साथ जीने का अधिकार। जीवन के अधिकार में क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। इसलिए, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ सभी उम्र के समलैंगिक और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। इसके बाद, यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान के आधार पर घृणा अपराधों सहित यातना या दुर्व्यवहार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। गरिमा और किसी व्यक्ति की स्वायत्तता से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे यह भी कहा गया कि निजता के अधिकार की सुरक्षा मानवीय गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता है। हाल के एक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। निजता के आधिकार में निजी और पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत अंतरंगता, प्रजनन, विवाह और यौन अभिविन्यास के सम्मान के अधिकार का संरक्षण भी शामिल है। न्यायालय द्वारा आगे यह भी कहा गया कि निजता का अधिकार एक अंतर्निहित अधिकार है जिसे जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से तक से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि गोपनीयता केवल घर पर क्या करती है इसके बारे में नहीं है बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि किसी के जीवन को कैसे जीना है।

दिए गए फैसले का वयस्कों के बीच सहमति से निजी समलैंगिक कृत्यों के अपराधीकरण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। समलैंगिक और समलैंगिक समानता (एनसीजीएलई) बनाम न्याय मंत्री के राष्ट्रीय गठबंधन में, दक्षिण अफ्रिका के संवैधानिक न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि किसी व्यक्ति की कामुकता, लिंग या यौन अभिविन्यास का पहलू प्रत्येक व्यक्ति में उस हद तक निहित है जितना कि एक व्यक्ति लिंग या कामुकता के उन पहलुओं को अपने घर पर पीछे नहीं छोड़ सकता। निजता का अधिकार व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में स्वायत्त विकल्प बनाने की अनुमति देता है। गोपनीयता, गरिमा और स्वायत्ता के अधिकार से संबंधित निर्णयों का यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है।

संविधान की प्रस्तावना न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इसलिए उन लोगों के लिए जो अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के हकदार हैं, यह बताता है कि राज्य कानून के समक्ष किसी भी व्यक्तिगत समानता या कानून के समक्ष समान सुरक्षा इनकार नहीं करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को निजता और व्यक्तिगत गरिमा के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 23 जो भिखारी के रूप में मानव तस्करी और मजबूर श्रम के अन्य समान रूपों का निषेध करता है और इन प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन एक आपराधिक अपराध होगा।

संविधान समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है और यौन अभिविन्यास, संप्रदायवाद, धर्म या विश्वास के आधार पर भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता है।

संविधान सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों और अन्य लाभों की गारंटी भी देता है। हालाँकि, तीसरे पक्ष (ट्रांसमीटर) के साथ भेदभाव जारी है। संविधान सभी क्षेत्रों में समानता की गारंटी देता है लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या इसे लागू किया जा रहा है। संविधान के अनुसार, मौलिक अधिकार अध्याय के तहत अधिकांश सुरक्षा केवल नागरिकों तक सीमित कुछ अधिकारों वाले सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। इस खंड के बिना, संविधान अधिकार धारकों के बीच भेदभाव नहीं करता है। लेकिन आधिकारिक पहचान दस्तावेज एक सार्वजनिक पहचान प्रदान करते हैं। जिन उपकरणों में भारतीय राज्य मानवता को परिभाषित करता है, उनमें लिंग पहचान सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य श्रेणी है। लिंग आधारित पहचान दस्तावेज भारतीय राज्य द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक स्वामित्व का एक अभिन्न अंग है। केवल उभयलिंगीपन को स्वीकार करने और हिजड़ों को महिलाओं के रूप में, या एक तीसरे पक्ष के रूप में स्वीकार करने से इनकार करने की भारत की नीति (यदि हिजड़ा मांग करता है), उन्हें उन कई अधिकारों से वंचित करता है जो भारतीय नागरिक प्रदान करते हैं। इन अधिकारों में मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिार, विवाह का अधिकार, पासपोर्ट और शेरर कार्ड के स्वामित्व का दावा करने का अधिकार, ड्राइविंग लाइसेंस, अध्ययन का अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य, और बहुत कुछ शामिल हैं। इस तरह की कमी हिजड़ों को भारतीय समाज के ताने-बाने से अलग करती है।